

F.No. CD-11012/01/2022-Coord.  
Government of India  
Ministry of Road Transport & Highways  
(Coordination Section)  
Transport Bhawan, 1, Parliament Street, New Delhi - 110001

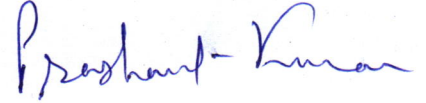
---

Dated the 10<sup>th</sup> May, 2022

OFFICE MEMORANDUM

**Subject: - Monthly Summary for the Cabinet for the Month of April, 2022.**

A copy of the unclassified portion of the Monthly Summary (Both English & Hindi) for the Cabinet pertaining to the Ministry of Road Transport and Highways for the month of April, 2022 is enclosed herewith for information.



(Prashant Kumar)  
Section Officer (Coordination )

Encl. As above

To,

1. All members of the Council of the Ministers
2. Deputy Chairman, NITI Aayog, Yojana Bhavan, New Delhi
3. All Members of NITI Aayog, Yojana Bhavan, New Delhi. (10 spare copies)
4. Cabinet Secretary , Rashtrapati Bhavanm New Delhi
5. All Secretaries to Government of India
6. Information Officer, PIB , Shastri Bhavan, New Delhi

## Ministry of Road Transport and Highways

**Subject: Monthly Summary for the Cabinet for the month of April, 2022.**

1. **Award and Construction of National Highways:** The Ministry has constructed 578 Km of National Highways in April 2022-23 as compared to 853 km constructed in April 2021-22. The award figure is 201 km during this month as compared to 311 Km in April previous year.
2. **Changes in Bidder Eligibility criteria of NH projects under Hybrid Annuity Mode:** Ministry has amended the Standard RFP document of HAM Mode to incorporate provisions relating to Threshold Technical capacity prescribed for similar work experience for EPC works related to Major Bridges and Tunnels. This will enable NHAI to procure concessionaires having appropriate experience in Major Bridges/Tunnels for projects being executed under HAM mode.
3. **Extension of relief for Contractors/Developers of Road Sector in view of COVID-19 pandemic:** Ministry has extended the relief measures to the contractors /developers of Road Sector in view of COVID -19 pandemic till 31<sup>st</sup> October, 2022. Various relief measure include relaxation in Schedule H/G; Direct payment to approved sub-contractor through Escrow Account; reduction in Performance Security, Proportionate release of retention money; extension of time to contractors/concessionaires; waiver of penalty for delay in submission of performance Security/Bank Guarantee; extension of time to consultants; extension of concession period of BOT/TOT contracts on account of reduction in collection of user fee; compensation for loss in collection of fee and extension of Time to Concessionaire for achievement of Financial Closure in the Concession Agreements.
4. **Rain Water Harvesting on National Highways Corridors:** Ministry has issued guidelines for providing rainwater harvesting and artificial recharging on all the buildings and structures such as toll plaza building, wayside amenities, grade separated structure etc. which are to be developed as part of the project corridor.
5. **Mandatory fitness of motor vehicles through automated testing station:** Ministry has issued a notification dated 5th April, 2022 regarding mandatory fitness of motor vehicles only through an Automated Testing Station(ATS), registered in accordance with rule 175 of the Central Motor Vehicle Rules

1989. Heavy goods vehicles/heavy passenger motor vehicles with effect from 01.04.2023 onwards and medium goods vehicles/medium passenger motor vehicles and light motor vehicles with effect from 01.06.2024 onwards are to be go through mandatory fitness from ATS .

6. **NHAI Settles 60 Conciliation Cases in FY 2021-22:** Keeping its commitment to provide speedy resolution of disputes with contractors/concessionaires through conciliation, NHAI has settled 60 cases for Rs. 4,076 crore against the claimed amount of Rs. 14,590 crore during FY 2021-22. The authority resolved these cases with a settlement amount that was about 28 percent of the total claimed amount. Last year, NHAI settled 60 cases for Rs. 5,313 crore against the claimed amount of Rs. 14,207 crore
7. **Signing of MoU between NHLML with State Government of Himachal Pradesh:** NHLML (National Highways Logistics Management Limited), a SPV Company of this Ministry has signed a MoU with State Government of Himachal Pradesh for construction of rope-ways in Himachal Pradesh under the ambitious Parvatmala Yojana. This is a significant MoU which will facilitate a unique, eco-friendly, scenic and seamless travel experience for tourists. By leveraging world class technology, 7 ropeway projects of total length 57.1km at total cost of Rs 3,232 Crore will be constructed in the State.
8. **Meeting between Hon'ble Minister (RT&H) and Brazilian Minister of Mines and Energy:** Union Minister for Road Transport and Highways, Shri Nitin Gadkari met the Brazilian Delegation led by Brazilian Minister of Mines and Energy Mr Bento Albuquerque on 20/04/2022 . The Minister interacted with a business delegation comprising of Brazilian industry representatives from the Sugar, Ethanol and Automobile industries along with the representatives from the Indian Automobile Industry. The Minister emphasised on greater cooperation between India and Brazil on usage of Ethanol and reducing carbon emissions across various sectors to strengthen both the economies.
9. **Standing Finance Committee (SFC) meetings:** In the month of April, 2022, 10 projects of length 250 km and total capital cost of Rs. 4,185 Cr. were appraised by SFC and recommended for approval.

\*\*\*\*\*

## सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

विषय: मंत्रिमंडल के लिए अप्रैल, 2022 माह का मासिक सारांश।

- 1. राष्ट्रीय राजमार्गों को सौंपना और निर्माण :** मंत्रालय ने अप्रैल 2021-22 में 853 किलोमीटर के निर्माण की तुलना में अप्रैल 2022-23 में 578 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया है। पिछले वर्ष अप्रैल में 311 किलोमीटर की तुलना में इस महीने के दौरान सौंपा गया आंकड़ा 201 किमी है।
- 2. हाइब्रिड वार्षिकी मोड के तहत रारा परियोजनाओं के बोलीदाता पात्रता मानदंड में परिवर्तन :** मंत्रालय ने प्रमुख पुलों और सुरंगों से संबंधित ईपीसी कार्यों के समान कार्य अनुभव के लिए निर्धारित सीमा तकनीकी क्षमता से संबंधित प्रावधानों को शामिल करने के लिए एचएएम मोड के मानक आरएफपी दस्तावेज में संशोधन किया है। यह एनएचएआई को एचएएम मोड के तहत निष्पादित की जा रही परियोजनाओं के लिए प्रमुख पुलों/सुरंगों में उपयुक्त अनुभव वाले रियायतग्राहियों की व्यवस्था करने में सक्षम बनाएगा।
- 3. कोविड-19 महामारी को देखते हुए सड़क क्षेत्र के ठेकेदारों/डेवलपर्स के लिए राहत में विस्तार :** मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी को देखते हुए सड़क क्षेत्र के ठेकेदारों/डेवलपर्स के लिए राहत उपायों को 31 अक्टूबर, 2022 तक बढ़ा दिया है। विभिन्न राहत उपायों में अनुसूची एच/जी में छूट; एस्क्रो खाते के माध्यम से अनुमोदित उप-ठेकेदार को सीधे भुगतान; निष्पादन प्रतिभूति में कमी, प्रतिधारण राशि को आनुपातिक जारी करना; ठेकेदारों/रियायतग्राहियों के लिए समयाविस्तार; निष्पादन प्रतिभूति/बैंक गारंटी जमा करने में देरी के लिए दंड से छूट; परामर्शदाताओं की समयावधि का विस्तार; प्रयोक्ता शुल्क के संग्रहण में कमी के कारण बीओटी/टीओटी अनुबंधों की रियायत अवधि का विस्तार; शुल्क के संग्रहण में हानि की क्षतिपूर्ति और रियायत अनुबंधों में वित्तीय समापन हासिल करने के लिए रियायतग्राही को समयाविस्तार शामिल है।
- 4. राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों पर वर्षा जल संचयन :** मंत्रालय ने परियोजना गलियारे के हिस्से के रूप में विकसित किए जाने वाले टोल प्लाजा भवन, मार्गस्थ सुविधाएं, ग्रेड सेपरेटेड संरचना आदि जैसे सभी भवनों और संरचनाओं पर वर्षा जल संचयन और कृत्रिम रिचार्जिंग उपलब्ध कराने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
- 5. स्वचालित परीक्षण स्टेशन के माध्यम से मोटर वाहनों की फिटनेस अनिवार्य करना :** मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 175 के अनुरूप पंजीकृत किसी स्वचालित परीक्षण स्टेशन (एटीएस) के माध्यम से मोटर वाहनों की फिटनेस अनिवार्य करने के संबंध में 5 अप्रैल, 2022 को एक अधिसूचना जारी की है। 01.04.2023 से भारी माल वाहनों/भारी यात्री मोटर वाहनों और 01.06.2024 से

मध्यम माल वाहनों/मध्यम यात्री मोटर वाहनों और हल्के मोटर वाहनों को एटीएस के माध्यम अनिवार्य रूप से फिटनेस कराना होगा।

6. एनएचआई ने वित्त वर्ष 2021-22 में 60 सुलह मामलों का निपटारा किया :

सुलह के माध्यम से ठेकेदारों / रियायतग्राहियों के साथ विवादों के त्वरित निपटान करने की अपनी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए, एनएचआई ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 14,590 करोड़ रुपये की दावा की गई राशि के बजाय 4,076 करोड़ रुपये से 60 मामलों का निपटान किया है। प्राधिकरण ने इन मामलों को निपटान राशि से सुलझाया, जो कुल दावा राशि का लगभग 28 प्रतिशत थी। पिछले वर्ष, एनएचआई ने 14,207 करोड़ रुपये की दावा राशि के बजाय 5,313 करोड़ रु. से 60 मामलों का निपटान किया था।

7. हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार और एनएचएलएमएल के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर :

एनएचएलएमएल (नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड), इस मंत्रालय की एक एसपीवी कंपनी ने महत्वाकांक्षी पर्वतमाला योजना के तहत हिमाचल प्रदेश में रोप-वे के निर्माण के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन है, जिससे पर्यटकों के लिए एक अद्वितीय, पर्यावरण अनुकूल, दर्शनीय और निर्बाध यात्रा अनुभव की सुविधा उपलब्ध होगी। विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी का लाभ उठाकर राज्य में कुल 3,232 करोड़ रुपये की लागत से 57.1 किमी की कुल लंबाई की 7 रोपवे परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा।

8. माननीय मंत्री (सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय) और ब्राजील के खान और ऊर्जा मंत्री के बीच बैठक :

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने 20/04/2022 को ब्राजील के खान और ऊर्जा मंत्री श्री बेंटो अल्बुकर्क के नेतृत्व में ब्राजील के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। मंत्री ने भारतीय ऑटोमोबाइल उद्योग के प्रतिनिधियों के साथ ब्राजील के चीनी, इथेनॉल और ऑटोमोबाइल उद्योगों के प्रतिनिधियों के एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की। मंत्री ने दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में इथेनॉल के उपयोग और कार्बन उत्सर्जन को कम करने पर भारत और ब्राजील के बीच अधिक सहयोग पर जोर दिया।

9. स्थायी वित्त समिति (एसएफसी) की बैठकें :

एसएफसी द्वारा अप्रैल, 2022 के महीने में 250 किमी लंबाई की और 4,185 करोड़ रुपये की कुल पूंजीगत लागत की 10 परियोजनाओं का मूल्यांकन किया गया था और अनुमोदन के लिए सिफारिश की गई थी।

\*\*\*\*\*